

पहले मुख्य समाचार।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेल ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। कहा- डबल इंजन की सरकार में नौजवानों को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर।
- दावोस में हुए छप्पनवें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने किए तीन लाख करोड़ रुपये के करार। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा- बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कर रही है निवेशकों को आकर्षित।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों के प्रति केन्द्र सरकार ने किया आश्वासन। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा-संविधान के दायरे में ही की जाएंगी सभी कार्रवाई।
- आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रेल ओवर ब्रिज और फोर लेन मार्ग पर फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर सहित पूर्वांचल में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण और बेहतरीन कनेक्टिविटी के चलते प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।

यह डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बनाकर के प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्केलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में उन्हीं के जनपद में उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर डेढ़ करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है।

स्विट्जरलैंड के दावोस में सम्पन्न हुए छप्पनवें विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने एक सौ उन्नीस रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लिया। लखनऊ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री खन्ना ने बताया कि इन बैठकों में प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों के साथ तीन लाख करोड़ के इकतीस करार किए। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक है। यहां की कनेक्टिविटी, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित माहौल के चलते यह निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए और उसमें सबसे बड़ा एमओयू जो हुआ है वो एएम ग्रीन का है। नीदरलैंड की कंपनी है, जिसने एआई रेसू वन गीगावाट डाटा सेंटर का एक एमओयू किया है। यह लगभग दो करोड़ सात लाख का है, तो यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री खन्ना ने बताया कि जिन क्षेत्रों में समझौते किए गए उनमें मुख्य रूप से डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल आदि शामिल हैं।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय ए.आई.मंथन कार्यशाला शुरू हुई। इस कार्यशाला का विषय 'उच्च और तकनीकी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियां और अवसर' है। कार्यशाला में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव सहित करीब दो सौ नब्बे शिक्षाविद सम्मिलित हो रहे हैं। इस अवसर पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति विनय कुमार पाठक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग कर शिक्षण को कई गुना बेहतर बनाया जा सकता है।

तो आज जो अपॉर्चुनिटीज है हम लोग के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तो इस पर यह एआई मंथन है। तो पहला तो हर बच्चे को अब हम इस टेक्नोलॉजी से उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे प्रोफेसर बात करते रहते कि लर्निंग ऑन इट्स ओन पेस तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। उसके हिसाब से उसका चैट बोट बना सकते हैं। उसके हिसाब से उसको ट्यूटर बना सकते हैं।

इससे पहले राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के एआई स्टार्टअप्स का अवलोकन किया।

पद्म पुरस्कार दो हजार छब्बीस से सम्मानित होने वाली विभूतियों में प्रदेश के ग्यारह लोग शामिल हैं। इनमें एन. राजम को पद्म विभूषण सम्मान, जबकि अन्य दस लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया जायेगा। लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी, वैज्ञानिक और फिल्म अभिनेता डॉ. अनिल रस्तोगी को कला एवं अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जायेगा। श्री रस्तोगी ने कहा कि पद्म पुरस्कार के लिये चुना जाना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है।

यह पद अवार्ड जो है, जाहिर है कि जो मिला है अगर मुझे तो मैं तो इसको बड़ा सम्मान मानता हूँ और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ अपने कलाकारों को जिनके साथ मैंने काम किया है, अपने गुरुओं को जिनसे मैंने सीखा है और सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरी सीडीआरआई को क्योंकि सीडीआरआई में रह कर के मैंने साइंस और थिएटर ऑलमोस्ट मैंने पैरेलल किया है दोनों तो अगर मैं सीडीआरआई में नहीं होता तो शायद मैं आज ना थिएटर कर रहा होता, ना फिल्में कर रहा होता, ना सीरियल कर रहा होता।

केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी. के नए दिशानिर्देश शिक्षा परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए हैं और इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी कार्यवाई संविधान के दायरे में ही की जाएगी।

डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा इसमें यूजीसी हो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो इसकी दायित्व रहेगी कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा और यह तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह दो अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र से पहले कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा।

राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। उससे चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पर दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिव्हेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारु रूप से चलाने में योगदान करें।

केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण कल नई दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और बजट तैयारियों में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियों का निस्तारण, नोटिस जारी किये जाने तथा इस पर हो रही सुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण में छह फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। सत्ताइस फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। जबकि छह मार्च, दो हजार छब्बीस को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से एसआईआर के कार्य में पूर्ण सहयोग करने और अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाये जाने के लिए भी आह्वान किया।

उच्चतम न्यायालय ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड हमले के मामलों की संख्या और अदालतों में उनकी स्थिति सहित कई तरह की जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने पीड़ितों की सहायता के लिए पुनर्वास उपायों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं।

पीलीभीत और शामली सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल तेज हवा के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं अमरोहा और गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने तथा वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है।
